कंपनी आएगी, वह रोजगार बंद करने की जगह उसको और बढ़ावा देने के लिए आएगी, इसलिए ऐसा प्रयास होगा कि भविष्य में इसमें और ज्यादा लोग काम करें।

DR. SASMIT PATRA: Sir, I would like to know from the hon. Minister as to why we are not providing the Numligarh Refineries Limited to a strategic buyer. Instead, we are transferring the management control to a Central Public Sector Enterprise. Is there a specific reason behind?

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, it is a very relevant question. NRL is a separate and legal entity. If you look at the Kochi Refinery, it is an integral part of BPCL whereas this is a subsidiary. Because of geo-strategic location and the expansion plan of the NRL where an investment of ₹22,000 crore will go in, it is going to further enhance its production. Due to geo-strategic location, it is important for India and that is why it has been given to a CPSE. The option is that.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, can I add a sentence?

MR. CHAIRMAN: Yes, please. The Cabinet Minister always has a right to add.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Thank you, Sir. The question is very relevant. Here, the crude of Oil India Limited or the Assam crude is essentially refined in the NML. Because there is a logistical and scaling up provision also, it has to go through that refinery and that is one of the considerations. More importantly, it is a part of the Assam Accord. So, we want to respect that sentiment.

DR. L. HANUMANTHAIAH: Sir, due to a change in the ownership after privatisation, is there a job loss in the company? Would the benefits, which the employees are getting, continue even after the change of ownership?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सभापति जी, मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूँ।

MR. CHAIRMAN: Next Question.

सरकारी कार्यालयों द्वारा वाहनों को किराए पर लिया जाना

*231. **श्रीमती विप्लव ठाकुर**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ संस्थानों में विभिन्न ट्रैवल एजेन्सियों से वाहन किराये पर लिये जाते हैं?

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मंत्रलयों/विभागों/अधीनस्थ संस्थानों द्वारा किराये पर लिए गए वाहनों में से अधिकतर वाहन व्यावसायिक प्रयोग के लिए अधिकृत नहीं है, जिससे सरकार को प्रति माह राजस्व के रूप में एक बड़ी धनराशि की हानि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने के बारे में विचार कर रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): (क) से (घ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। यह सच है कि मंत्रालय/विभाग/अधीनस्थ संस्थाएं विभिन्न आउटसोर्स एजेंसियों से वाहन किराए पर लेती हैं। चूंकि सभी मंत्रालय/विभाग अपनी-अपनी कार्यात्मक जरूरतों के अनुसार आउटसोर्स्ड वाहन किराए पर लेते हैं, इसलिए वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में केन्द्रीय तौर पर कोई डाटा नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 149 के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों द्वारा माल और सेवाओं का प्रापण (जिनमें वाहनों का किराए पर लिया जाना भी शामिल है) अनिवार्यतः गवर्नमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (जैम) के माध्यम से करना होता है जिसका उद्देश्य लोक प्रापण में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है। इसके अलावा, जैम की वाहनों को किराए पर लिए जाने की शर्तों के अनुसार किराए पर लिए जाने वाले वाहन, व्यावसायिक वाहनों के तौर पर उसी राज्य में रजिस्टर्ड होने चाहिए जिसमें उनकी सेवाएं मांगी गई हैं।

Hiring of vehicles by Government offices

†*231. SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that various Ministries/Departments/Subordinate Institutions of Government hire vehicles from different travel agencies;

(b) if so, the detail thereof;

(c) whether it is also a fact that most of the vehicles hired by Ministries/Departments/Subordinate Institutions are not authorised for commercial use thus causing a huge loss of revenue per month to Government; and

†Original notice of the question was received in Hindi.

(d) if so, action Government is considering to prevent such a corruption?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANURAG SINGH THAKUR): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Yes, Sir. It is fact that Ministries/Departments/Subordinate Institutions hire vehicles from various outsource agencies. As all Ministries/ Departments are hiring outsourced vehicles according to their respective functional requirements, no centralized data is maintained by Ministry of Finance in this regard.

(c) and (d) As per General Financial Rules 2017, Rule 149 the procurement of Goods and Services (including hiring of vehicles) by Ministries/Departments is mandatorily to be made through Government e-Marketplace (GeM) which aims to enhance transparency and efficiency in public procurement. Further, as per GeM terms and conditions for hiring of vehicles, the vehicles to be hired should be registered as a commercial vehicle in the same State as the service is requested in.

श्रीमती विप्लुव ठाकुर: सभापति जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें इन्होंने कहा है कि कोई डेटा नहीं रखा गया है। मैं यह जानना चाहती हूं कि ये प्राइवेट गाड़ियों के लिए जो रिक्विज़िशन देते हैं - सर, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, क्या वे अपनी रिक्विज़िशन में यह बताती हैं कि उनको कितनी गाड़ियाँ चाहिए? मैं जानना चाहती हूं कि जो उनकी need होती है, क्या उससे ज्यादा गाड़ियाँ ली जाती हैं एवं क्या डिपार्टमेंट्स में इसका कोई ब्योरा रखा गया है?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सभापति जी, क्योंकि माननीय सदस्या मेरे गृह प्रदेश हिमाचल प्रदेश से आती हैं, इसलिए मुझे इन्हें थोड़ा विस्तार से उत्तर देना पड़ेगा। Sir, this Government e-Marketplace is the idea of Shri Narendra Modi to bring in more transparency into the system. That is why, to facilitate the online procurements for the common use of goods and services, this has been put in place. What has been the achievement so far? Sir, the key highlights of Government e-Marketplace are that the number of buyers...

MR. CHAIRMAN: You have already given it in the answer.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सभापति जी, यह ब्योरा आन्सर में पूरा नहीं है। I will take just thirty seconds. The number of buyer organisations is 40,960; the number of

[श्री अनुराग सिंह ठाकुर]

sellers and service providers is 3,06,619; the number of products is 15,60,076; the number of services provided is 20,619; the number of orders placed is 28,55,597; the transaction value is ₹40,432 crore. As far as your question is concerned, Madam, this brings in more transparency. Only those companies which are registered locally and have the commercial numbers for the vehicles are being taken under this.

MR. CHAIRMAN: The second supplementary question.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, the demand is...

MR. CHAIRMAN: Thakurji, you have to keep in mind what I said. You have given an exhaustive reply. Still she asked...

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, the demand is given by the Departments in the allocated Budget.

श्रीमती विप्लव ठाकुर: सर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि commercial vehicles का जो टैक्स है, वह ज्यादा होता है। कई जगह इसका जो misuse होता है, private तौर से भी होता है और हमें revenue का loss ता है, क्या माननीय मंत्री जी इस बात से अवगत हैं?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सर, इससे काम करने वाला भी अवगत है और हम भी अवगत हैं। लोग टैक्स की चोरी न करें, तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर commercial vehicles के number plate का जो registration होगा, इसमें केवल उन्हीं को लेने की बात रखी गई है। उसकी जो guidelines हैं, उनमें यह बड़ा clearly specified है। जो departments Government e-Marketplace पर जाकर vehicles hire करते हैं, उनमें competition होता है और reverse bidding तक होती है।

श्री सभापति: प्रश्न संख्या 232.

Data on female foeticides

*232. SHRI NARESH GUJRAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government is planning to conduct any nationwide survey to maintain gender-wise data of foeticides, if so, the details thereof;

(b) the steps taken by Government to check the implementation of the